# गन्ने की पेराई से निजी मिल मालिकों का इनकार

**बीएस संवाददाता**
नई दिल्ली, 5 अगस्त

**उत्तर प्रदेश** में परिचालन कर रही निजी क्षेत्र की करीब 95 चीनी मिलों ने अक्टूबर से शुरू हो रहे 2014-15 पेराई सत्र में तब तक परिचालन नहीं करने का फैसला किया है, जब तक राज्य सरकार गन्ने के दाम को चीनी के दाम से जोड़ने का फैसला नहीं करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार सी रंगराजन ने चीनी उद्योग को बचाने के लिए गन्ने के भाव को चीनी के मूल्य से जोड़ने का सुझाव दिया था।

चीनी मिल मालिकों का आरोप है कि सरकार की गलत मूल्य निर्धारण नीति के कारण उन्हें प्रत्येक किलोग्राम चीनी की बिक्री पर साढ़े पांच रुपये का घाटा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चीनी कारोबार करीब 30,000 करोड़ रुपये का है। उत्तर प्रदेश के अग्रणी चीनी मिल मालिकों ने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले साल किए गए अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया और इसी वजह से उन्हें आज यह कदम उठाना पड़ रहा है। चीनी मिलों ने कहा, 'आज से चीनी मिलों में मरम्मत और रखरखाव का काम बंद कर दिया जाएगा और स्टाफ भी हटा लिया जाएगा। चीनी मिले व्यक्तिगत तौर पर भी सरकार को अपना नोटिस भिजवा देंगी।' इस सम्मेलन में बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक कुशाग्र बजाज, बलरामपुर चीनी मिल्स के प्रबंध निदेशक विवेक सरावगी, द्वारिकेश शुगर के गौतम मोरारका, उत्तर शुगर के बलराम अधलखा, डीसीएम श्रीराम के अजित श्रीराम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ऐंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तरुण साहनी भी मौजूद थे। केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है, लेकिन राज्य सरकारें भी राज्य परामर्श मूल्य घोषित करती हैं।

## बढ़ेगी मुश्किल

- राज्य में करीब 40 लाख किसान हैं चीनी मिलों पर निर्भर
- देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30 फीसदी
- इसमें से 96 निजी चीनी मिलों का है 92 फीसदी योगदान

बिजनेस स्टैन्डर्ड
6/8/14